शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक-41 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 06-13 अक्तूबर 2025 मूल्य पांच रूपये

स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से निकलते राजनीतिक संकेत और सन्देश

शिमला/शैल। प्रदेश के छः बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर जिस संख्या में लोग आये थे उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह सही अर्थो में आम जनमानस के व्यक्ति थे और उनकी प्राथमिकता यह प्रदेश था। यह भीड़ इस सरकार के लिये नहीं थी और न ही इस अवसर पर आये केंद्रीय नेताओं के लिये थी। यदि यह सरकार स्व. वीरभद्र सिंह की कृतज्ञ होती तो इस प्रतिमा के अनावरण के लिये इतना लम्बा समय न लगता। समय की यह लम्बाई ही सरकार और स्व. वीरभद्र सिंह के रिश्तों की कहानी ब्यान कर देती है। इस अवसर पर जिन नेताओं ने अपने-अपने विचार रखें और सरकार की प्रशंसा की वह सब महज रस्म अदायगी थे। लेकिन इस रस्म अदायगी में भी नेतृत्व को यह एहसास आवश्यक हो गया है की राजनीति और विकास की जो लकीर स्व. वीरभद्र सिंह प्रदेश में खींच गये हैं उससे इतर जाना जोखिम भरा होगा। क्योंकि यह सरकार चुनावों में दस गारंटीयां जनता को देकर आयी थी उनमें से कितनी पूरी हुई हैं इसका प्रमाण नेताओं के दावों और प्रैस विज्ञप्तियों में नहीं आंका जायेगा। उसका प्रमाण गांव में बैठा वह आदमी है जिसके पास इन गारंटीयों का प्रतिफल पहुंचना था। रोजगार का प्रमाण मल्टी टास्क जैसे वर्कर नहीं हो सकते सरकार को यह समझना होगा क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सरकार ही है। सरकार सत्ता संभालने के पहले

दिन से ही प्रदेश में कठिन वित्तीय स्थिति का डर खड़ा करती आयी है। इस डर को पुख्ता करने के लिये प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो जाने की चेतावनी तक जारी कर दी थी। पिछली सरकार द्वारा अंतिम छः माह में लिये फैसले बदल दिये थे। लेकिन आगे चलकर यह डर और चेतावनी ही सरकार के लिये कसौटी बन गयी। आम आदमी सरकार की कथनी और करनी पर नजर रखने लग पड़ा। इस नजर में जब यह आया कि मंत्रिमण्डल के गठन से पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिला दी गयी। जब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इन लोगों को पद त्यागने पड़े और आज तक सरकार का कामकाज ठीक चल रहा है तब यह सवाल स्वयं ही उठ गया कि इन नियुक्तियों की आवश्यकता क्या थी। जब सरकार ने राज्यपाल के लिये नब्बे लाख की गाड़ी खरीद ली और राजभवन ने यह कह दिया कि उन्होंने तो इसकी मांग ही नहीं की थी तब फिर सरकार की वित्तीय समझ पर सवाल उठ खड़े हुये। आज सरकार के हर फैसले को वित्तीय तराजू में तोलकर देखा जा रहा है। बढ़ते कर्ज का निवेश कहां हो रहा है अब यह सवाल भी पूछा जाने लग पड़ा है।

संगठन के नाम पर पिछले नवम्बर से प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक की सारी कार्यकारिणीयां भंग चल रही हैं। अब तक नई कार्यकारिणियों का गठन नहीं हो पाया है। अब प्रदेश अध्यक्ष भी नया बनाये जाने की चर्चा चल रही है और इस चर्चा में मुख्यमंत्री बनाम प्रतिभा सिंह आमने-सामने की स्थिति बनती जा रही है। मंत्रिपरिषद में भी एक पद खाली चल रहा है। इस खाली पद को भरने से लेकर मंत्री परिषद में भी फेरबदल करने तक चर्चाएं चला दी गयी हैं। प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि वीरभद्र सिंह की लीगेसी को नजरअन्दाज किया जाना पार्टी को भारी पड़ सकता है। इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर जिस कदर प्रदेश भर से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी है उससे स्व. वीरभद्र सिंह के समर्थकों की संख्या का अन्दाजा आसानी से लग जाता है। फिर स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह का अनुकरण करने का संकल्प इस अवसर पर लिया है उसका राजनीतिक प्रतिफल दूरगामी होगा। आज स्व. वीरभद्र सिंह के समर्थकों को एक राजनीतिक संबल चाहिये जो विक्रमादित्य सिंह में स्वभाविक रूप से है। विक्रमादित्य सिंह स्व. वीरभद्र सिंह के परंपरागत जनाधार का वारिस बनकर भविष्य की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं यह सन्देश भी इस आयोजन से गया है। इसमें यह देखना रोचक होगा कि विक्रमादित्य सिंह इस भीड़ के विश्वास को कितना बनाये रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इस समय प्रदेश कांग्रेस के हर खेमे का हर छोटा बड़ा नेता संगठन की इस दशा दिशा के लिये हाईकमान को दोषी ठहरा चुका है। सरकार बनने के बाद सरकार और पार्टी जनता में कितनी मजबूत हुई है इसका अन्दाजा सरकार के दौरान फेस किये गये स्थानीय निकायों, पंचायती संस्थाओं और सहकारी सभाओं के चुनावों के परिणामों से लगता है। लेकिन इस सरकार ने अपने राजनीतिक कौशल से इन चुनावों की स्थितियों को टाल दिया है। शायद अपने इस कार्यकाल में यह किसी भी चुनाव का सामना ही न कर पाये। इससे नेतृत्व को तो क्षणिक लाभ मिल जाता है परन्तु संगठन का दूरगामी नुकसान हो जाता है। संयोगवश व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र ने स्थितियां यहां तक पहुंचा दी है और इस प्रतिमा अनावरण आयोजन के अवसर ने इसका स्पष्ट संकेत और संदेश दे दिया है।

संस्कृत भाषा में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसी है:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा और सभी भाषाओं की जननी है। खगोल विज्ञान, आयुर्वेद जैसे विज्ञान पर आधारित प्रमुख विषय तथा ज्योतिष एवं योग जैसे विषय हमारे प्राचीन शास्त्रों के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह भारत की शाश्वत परंपराओं और चिकित्सा, भौतिक एवं गूढ़ विज्ञान तथा विभिन्न अन्य विषयों के गहन ज्ञान का भंडार है।

राज्यपाल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'विशिष्ट दीक्षांत महोत्सव' में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

संस्कृत और इसकी विशाल ज्ञान विरासत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर धर्म ग्रंथों में निहित ज्ञान के प्रति तेजी से जागरूक हो रहा है। यह बढ़ती जागरूकता साबित करती है कि आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने संस्कृत में शिक्षा प्रदान करने और लोगों के बीच इस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर शोध के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जनहित में इनके सार को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि हमारे संतों और विद्वानों ने मानवता, प्रकृति और पृथ्वी के कल्याण के लिए इन ग्रंथों की रचना की। उनके ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने से समाज लाभान्वित होगा।

केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सुरेंद्र दुबे ने भी सभा को संबोधित किया और समकालीन समाज में संस्कृत की प्रासंगिकता पर चर्चा की तथा विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की।

इससे पूर्व कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, वेद प्रकाश उपाध्याय, बालकृष्ण शर्मा और देवेंद्र नाथ त्रिपाठी और अन्य प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वानों और शिक्षाविदों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया।

इस अवसर पर समन्वयक प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी, रजिस्ट्रार प्रो. संतोष कुमार श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट विद्वान, संकाय सदस्य और छात्र भी उपस्थित थे।

जवाबदेही के साथ करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जवाबदेही के साथ इस्तेमाल करने के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि शब्दों में पवित्रता और शक्ति होती है। राज्यपाल बतौर मुख्यातिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित 'भारत में द्वेषपूर्ण भाषण और चुनाव राजनीति' विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। शब्दों से मित्रता और शत्रुता दोनों ही हो सकती है इसलिए इनका इस्तेमाल विनम्रता और गरिमा के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में हमारे वार्तालाप में शालीनता और सम्मान झलकना चाहिए।

राज्यपाल ने द्वेषपूर्ण भाषा की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के कुछ प्रतिनिधियों और वर्गों के बीच सार्वजनिक संवाद का गिर रहा स्तर निराशाजनक है। उन्होंने संवाद में मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए नागरिकों से उन लोगों का समर्थन न करने का आग्रह किया जो द्वेषपूर्ण या विभाजनकारी बयानबाजी करते हैं।

उन्होंने कहा कि हिंसा केवल शारीरिक कृत्यों तक ही सीमित नहीं है, आहत करने वाला और द्वेषपूर्ण भाषण भी हिंसा का एक रूप है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश और समाज के हित में इसका पूरी तरह से खंडन करना चाहिए। राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय से युवा पीढ़ी को भाषा के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के प्रति संवेदनशील बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. योगेश सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की और द्वेषपूर्ण भाषा के कानूनी और नैतिक आयामों को उदाहरणों के साथ समझाते हुए अनुच्छेद 19 पर विस्तार से चर्चा की।

अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता विधि संकाय प्रो.अंजू वली टिकू ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संगोष्ठी के उद्देश्यों को रेखांकित किया। आईएलसी निदेशक प्रो. एल. पुष्प कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रदेश में लोगों को मिल रहीं आधुनिक उपचार सुविधाएं: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक पहल की हैं। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला में उन्नत उपकरण, वित्तीय कवरेज के लिए हिम केयर योजना और पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर जैसी पहल शामिल हैं। प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार, कार्यबल को सुदृढ़ करने, दुर्गम क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने और अपने नागरिकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई सुविधाओं के सृजन के दृष्टिगत निरंतर निवेश कर रही है, साथ ही मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है जिसमें ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर के साथ नया ओपीडी और पीईटी ब्लॉक तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में एक पीईटी स्कैन मशीन शामिल है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। मरीजों को अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाणा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जा रहा है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, विविध शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने और पहुंच में सुधार लाने के लिए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। प्रसव पूर्व देखभाल को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिलासपुर और किन्नौर जैसे कुछ जिलों में समय पर प्रसव पूर्व जांच के लिए लगातार उच्च कवरेज दी जा रही है।

हिम केयर योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिससे वित्तीय बोझ कम होने के साथ स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच की राह भी सुगम हो रही है।

सिरमौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने जैसी पहल धरातल पर सेवाओं को बेहतर बनाने का शानदार प्रयास है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उन्नयन और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना शामिल है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य में डिजिटल गवर्नेंस अभियान के तहत एक वर्ष में रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की

शिमला/शैल। वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण अभियान को अभूतपूर्व सफलता हासिल हो रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में लोग अब घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का सुगमता से उपयोग कर पा रहे हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में लोगों को रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को प्रमुखता प्रदान करते हुए राज्य के विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली को अपना रहे हैं। वर्ष 2023 में पोर्टल के माध्यम से लगभग 14.97 लाख सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई है और इस वर्ष के आगामी महीनों में वृद्धि का अनुमान है।

मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया गया है। वर्ष 2022 में 113 सेवाएं प्रदान की जा रही थी और वर्ष 2025 में ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़कर 436 हो गई है। वर्तमान सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त इन सेवाओं में चार गुणा की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह संख्या 217 और वर्ष 2024 में 251 दर्ज की गई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी एवं नवाचार गोकुल बुटेल ने कहा कि डिजिटल सेवाओं ने नागरिकों की सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिक किसी भी स्थान से कभी भी आवेदन कर सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही हैं। ये सेवाएं प्रदेशभर में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुलभ, पारदर्शी और कुशल डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी विभागों को कागज, उपस्थिति और नकदी रहित व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कुछ तहसीलों में शुरू की गई एक पायलट परियोजना के तहत अब बिना सरकारी कार्यालय जा कर संपत्ति का पंजीकरण करवाना संभव हो गया है। सरकार की इस पहल को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य विभागों को भी इसी तरह की डिजिटल नवाचारों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सोलन के वाकनाघाट में बनेगी साईबर सिटी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जिला सोलन

के वाकनाघाट में साईबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। यह साईबर सीटी 650 बीघा भूमि पर बनेगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग कार्यशील होंगे।

मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजना से जुड़े विस्तृत ब्लू प्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रमुख क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्ट केन्द्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशाला भी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कांगड़ा के चौतड़ू और जिला शिमला के मैहली में स्थापित किए जा रहे आईटी पार्क का निर्माण दिसम्बर, 2025 तक पूरा किया जाए।

शासन में डिजिटल सेवाओं की महत्ता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को अपने कार्यों को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि उत्कृष्ट एवं नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को एक क्लिक के माध्यम से लोगों के घर-द्वार पर पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए और कार्यालयों में पारदर्शिता लाने व कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-फाईल प्रबंधन व नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निपुण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वह कार्यालय में इसे अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की ऑनलाईन निगरानी के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बॉयोमेट्रिक्स से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आशीष सिंहमार, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. निपुण जिन्दल, आयुक्त श्रम एवं रोजगार वीरेन्द्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के एनएसए में समायोजन और तम्बाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओकओवर शिमला से 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 एनएसए में समायोजन और

स्वास्थ्य विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित तम्बाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 योजना के अंतर्गत 241 'एम्बुलेंस' प्रदेश भर मे क्रियाशील हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आज 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को इस बेड़े में शामिल किया गया है। इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा उपकरण जैसे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, आपातकालीन एम्बू बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, रक्तचाप निगरानी मशीन सहित 19 आपातकालीन जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस को सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों और अन्य दूरदराज के स्थानों पर तैनात किया जा रहा है ताकि आपात स्थितियों में मरीजों को स्थानांतरित किया जा सके। इन एम्बुलेंस में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ने तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देशभर में जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 हमारे युवाओं को तम्बाकू के खतरों से बचाने की प्रदेश सरकार की एक और सशक्त पहल है। यह अभियान 60-दिन यानी 8 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, जिसमें जागरूकता, रोकथाम और तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तम्बाकू हर साल भारत में 1.35 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है और गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याएं पैदा करता है। यह तथ्य भी सामने आया है कि तम्बाकू अक्सर अन्य नशों जैसे ड्रग्स की ओर ले जाता है इसलिए सबसे अच्छा निर्णय है कि तम्बाकू का सेवन बिल्कुल न करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के तम्बाकू उपयोग, ई-सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार अभियान चलाकर हुक्का बार और ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू दुकानों को नियंत्रित करने, विक्रेता लाइसेंस नियमों को लागू करने और शहरों व गांवों में आउटलेट्स की संख्या कम करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करें और हर स्कूल और गांव को तम्बाकू मुक्त बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 'तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा-निर्देशों' का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। संस्थानों के भीतर या आसपास तम्बाकू की बिक्री, उपयोग या विज्ञापन नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में निःशुल्क तम्बाकू त्याग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 109 नए दिशा केंद्रों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं ताकि लोग तम्बाकू छोड़कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और इससे दूर रहने की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने करसोग में 188 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के करसोग में लोगों को 188.8

करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने करसोग में 34.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन, 1.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विषयवाद विशेषज्ञ उद्यान कार्यालय भवन, करसोग में 29.51 लाख रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सामुदायिक केंद्र तुमण, 90.11 लाख रुपये की लागत से माहूंनाग मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, 71.57 लाख रुपये से मैंहडी ग्राम पंचायत के कार्य, 13 लाख रुपये से निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भन्थल, 32.74 लाख रुपये से ग्राम पंचायत सामुदायिक केंद्र सूई कुफरीधार और 13.75 लाख रुपये से संयुक्त कार्यालय भवन में अपना पुस्तकालय का लोकार्पण किया।

उन्होंने करसोग कस्बा एवं समीपवर्ती गांवों के लिए 55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना, 31.80 लाख रुपये से भकरोट-करसोग-सनारली - सैंज सड़क के उन्नयन कार्य, 13.18 करोड़ रुपये से खील से भगेलु सड़क के उन्नयन कार्य, 19.75 करोड़ रुपये की लागत से खील से भगेलु कैलोधार गरजूब के उन्नयन कार्य, 11.06 करोड़ रुपये की लागत से छलोग से बघेल मार्ग और 18.60 करोड़ रुपये की लागत से कैलोधार से सैंज सड़क के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रुपये की यूटिलिटी डक्ट परियोजना की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में 145 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जा रही यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण अधिकारियों को छोटा शिमला से विली पार्क तक निर्मित की जा रही 7 किलोमीटर लंबी डक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि छोटा शिमला से ओक ओवर तक इसका निर्माण कार्य

लगभग पूरा हो चुका है, इस कार्य को आगामी 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने सड़क की टारिंग और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला न केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बल्कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन गंतव्य है और इसके आकर्षण को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे शहर को तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी और पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वित होने से शिमला में पर्यटकों की आमद में वृद्धि होगी।

परियोजना के अन्तर्गत छोटा शिमला से विली पार्क, सचिवालय से होते हुए राजभवन से ओक ओवर तक तथा शेरे-ए-पंजाब पंजाब से लोअर बाजार से सीटीओ तक यूटिलिटी डक्ट का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। डक्ट में बिजली, पानी की लाइनों के साथ-साथ अन्य यूटिलिटी केबल बिछाई जाएंगी।

विधायक हरीश जनारथा, सुरेश कुमार और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री ने भर्ती और मरम्मत कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अवसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने सभी स्वीकृत पदों को तुरंत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में देरी न हो और स्कूलों में खाली पद शीघ्र भरे जा सकें। उन्होंने टीजीटी, जेबीटी, पंजाबी और ऊर्दू शिक्षकों तथा खेल छात्रावासों में डीपीई और कोच की भर्ती के लंबित मामलों पर नियमित रूप से निगरानी करने को कहा ताकि समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें।

रोहित ठाकुर ने सभी स्तरों पर शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी कठिनाई का सामना न करने पड़े। उन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षाओं में पीजीटी की नियुक्तियों की भी समीक्षा की और उप-निदेशकों को विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों द्वारा सफल उदाहरण और नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो पीजीटी अपनी पदोन्नति पोस्टिंग में समय पर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, उनकी पदोन्नति रद्द कर अगले योग्य उम्मीदवार को मौका दिया जाए।

रोहित ठाकुर ने कहा कि नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाए ताकि प्रस्ताव मन्त्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कोटखाई और पांवटा साहिब में केंद्रीय

विद्यालय स्थापित करने के लिए भी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रधानाचार्य पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया।

शिक्षा मंत्री ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से स्कूलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1320 से अधिक शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको लगभग 122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पीडीएनए फंड का सही उपयोग किया जाए और 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए तथा रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए ताकि बची हुई निधि को अन्य क्षतिग्रस्त स्कूलों को आवंटित किया जा सके।

स्कूल निरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने उप-निदेशकों (माध्यमिक, प्राथमिक और गुणवत्ता शिक्षा) को लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि शिक्षा मानकों और जवाबदेही में सुधार हो सके।

उन्होंने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना की समीक्षा भी की और अधिकारियों को सभी पात्र छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में 2023 से अब तक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों, सुधारों और पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। अतिरिक्त शिक्षा सचिव शुभकरण सिंह, परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, निदेशक, स्कूल शिक्षा आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

उप-मुख्य सचेतक ने केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का किया भ्रमण

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने राजस्थान के जयपुर स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। यह देश के प्रमुख वन्यजीव और पक्षी अभयारण्यों में से एक है और अपनी अद्भुत जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य व दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि इस अभयारण्य में लगभग 150 देशी और विदेशी प्रजातियों के पक्षी और 200 से अधिक प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। भ्रमण के दौरान उप-मुख्य सचेतक विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों को ध्यानपूर्वक देखा, उनके प्राकृतिक आवास के बारे में जाना और उनके संरक्षण तथा सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान न केवल वन्यजीवन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यान के प्रबंधन और संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें।

वह परिवर्तन स्वयं बनें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

इस अराजकता का अन्तिम परिणाम क्या होगा?

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जिस तरह के प्रमाणिक आरोप राहुल गांधी अपनी पत्रकार वार्ताओं पर लगाते जा रहे हैं और इन आरोपों की विधिवत जांच करवाये जाने की बजाये जिस तरह का रुख चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर अपनाती जा रही है वह अब चिंताजनक होता जा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग के रुख के बाद जब यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में इस मांग के साथ पहुंचा कि राहुल गांधी के आरोपों की जांच के लिये एक एसआईटी गठित की जाये और शीर्ष अदालत ने इस मांग को अस्वीकारते हुये इस आयोग के समक्ष ही उठाने का निर्देश दिया तब केन्द्र सरकार चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय सब एक साथ सवालों के दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि देश में लोकतांत्रिक सरकार के गठन की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनाव आयोग को सौंपी गयी है। चुनाव आयोग का गठन एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया है। चुनाव के दौरान सारा प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग को जवाब देह होता है। सरकार चुनाव आयोग को हर तरह से सहयोग करने के लिये बाध्य होती है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के होते हुये भी यदि चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग जायें और सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी निष्पक्ष जांच करवाये जाने से पीछे हट जाये तो यह स्वीकारना ही होगा कि देश किसी अप्रत्याशित की ओर बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी के आरोप जिस तरह के दस्तावेजी प्रमाणों के साथ लगाये जा रहे हैं उन पर देश का बहुसंख्यक वर्ग विश्वास करता जा रहा है। क्योंकि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर जिस तरह से पीछे हट गयी है उससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि यह वोट चोरी सत्तारूढ़ सरकार के लिये ही की जा रही है। इसका सबसे निराशाजनक पक्ष तो यह है कि शीर्ष अदालत भी अपरोक्ष में संविधान की रक्षक होने की बजाये सरकार की रक्षक होती जा रही है। ऐसे में जब केन्द्र सरकार चुनाव आयोग और देश का सर्वोच्च न्यायालय भी एक ही स्वर में गायन करना शुरू कर दे तो आम आदमी कहां और किसके पास जाये यह बड़ा सवाल हो जाता है। आज जो स्थितियां निर्मित होती जा रही हैं उनमें अनायास ही आम आदमी पिछले ग्यारह वर्षों में जो कुछ घटा है उस पर नजर दौड़ाना शुरू कर देता है। आम आदमी के सामने जब यह आता है कि जिस भी दल के किसी भी नेता पर अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसने अपने दल को छोड़कर भाजपा में शरण ले ली तो उसके खिलाफ सारी जांच बन्द हो गयी। आज भाजपा में दूसरे दलों से आये नेताओं की संख्या मूल भाजपाइयों से ज्यादा बढ़ जायेगी। आज भाजपा का राजनीतिक चरित्र सत्ता में बने रहने के लिये कुछ भी करने वालों की श्रेणी में आ गया है। भाजपा के इस सता मोह ने भाजपा को अपने ही आकलन में बहुत नीचे ला खड़ा कर दिया है। जिस पच्चहतर वर्ष की आयु सीमा के स्वघोषित सिद्धांत से लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आदि को मार्गदर्शक मण्डल में भेज दिया गया था वह नियम आज अपने लिये अप्रसांगिक हो गया है। जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती जा रही है उससे हर चुनाव में किया गया वायदा अब जवाब मांगने लग गया है। हर एक के खाते में पन्द्रह लाख आने, हर साल दो करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का वायदा हर जुबान पर आ गया है। महंगाई पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गयी है। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जो लोग बैंकों का हजारों करोड़ लेकर विदेश भाग गये थे उनमें से एक भी आज तक वापस नहीं आया है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पायी है। सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के नाम पर देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या मुस्लमानों में से भाजपा के कितने सांसद और विधायक हैं? क्या इसका जवाब आ पायेगा। कोविड काल में जो संविधान डॉ.भागवत के नाम से वायरल हुआ था उसमें महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों को किस तरह के अधिकार दिये गये थे उसकी झलक देश के मुख्य न्यायाधीश पर भरी अदालत में जूता उछाले जाने से सामने आ चुकी है। आज पूरा दलित समाज इस पर चर्चाओं में जुट गया है। यह जूता कांड देश के दूसरे भागों में भी फैलने लग गया है। क्योंकि इसकी निंदा करने की बजाये जिस तरह से इसे जायज ठहराया जा रहा है वह अपने में चिंता जनक है। कुल मिलाकर देश में बड़े स्तर पर अराजकता का वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसके परिणाम घातक होंगे। वोट चोरी के आरोपों की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिये। इस जांच से बचने का जितना प्रयास किया जायेगा वह घातक होगा। इससे अराजकता ही फैलेगी।

कृषि क्षेत्र में जीएसटी की नई दरें किसानों के लिए वरदान

किसानों की आय बढ़ाने का काम करेगी जीएसटी की नई दरें

शिवराज सिंह चौहान
कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार

किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती सरल हो, उत्पादन की लागत घटे और किसान को अधिक मुनाफा हो, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। अन्नदाताओं का जीवन बदलना और कृषि को विकसित बनाना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भी है और संकल्प भी। उनके निर्णयों, नीतियों और योजनाओं के केंद्र में हमेशा किसान रहते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा किए गए संशोधन इसी किसान हितैषी सोच को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म का जो संकल्प लिया था आज वह नए भारत की समृद्धि का आधार बन रहा है।

देश की आम जनता और किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीएसटी दरों में व्यापक सुधार किए गए हैं। यह सुधार हमारी कृषि व्यवस्था को गति और किसानों को प्रगति देने वाले हैं। इन सुधारों से देश के 10 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले जहां कृषि उपकरणों पर 18% तक जीएसटी देना पड़ता था, अब यह दर घटाकर केवल 5% कर दी गई है। इसका मतलब है कि हर किसान की जेब में हजारों रुपये की सीधी बचत होगी।

उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान 35 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर खरीदता था तो पहले उसे लगभग 6. 5 लाख रुपये (अनुमानित) खर्च करने पड़ते थे। अब यही ट्रैक्टर करीब 6.09 लाख रुपये में मिलेगा और किसान को लगभग 41 हजार रुपये की बचत होगी। 45 एचपी ट्रैक्टर पर करीब 45 हजार रुपये और 50 एचपीट्रैक्टर पर 53 हजार रुपये की सीधी बचत होगी। 75 एचपी ट्रैक्टर पर किसानों को लगभग 63 हजार रुपये का लाभ होगा। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, पावर टिलर पर करीब 12 हजार, धान रोपण यंत्र पर 15 हजार और थ्रेशर पर लगभग 14 हजार रुपये की बचत होगी। पावर वीडर और सीड-ड्रिल जैसे उपकरणों पर भी 5 से 10 हजार रुपये तक की बचत होगी। नए सुधारों से कटाई और बुवाई की बड़ी मशीनें भी किसानों को सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। 14 फीट कटर बार पर लगभग 1.87 लाख रुपये, स्क्वायरबेलर पर लगभग 94 हजार रुपये और स्ट्रॉरीपर पर करीब 22 हजार रुपये किसानों की जेब में बचेंगे। मल्चर, सुपरसीडर, हैप्पीसीडर और स्प्रेयर भी अब पहले से सस्ते हो गए हैं।

कृषि को अधिक लाभदायक बनाने के लिए मशीनीकरण आवश्यक है। स्प्रिंकलर, ड्रिपइरिगेशन, कटाई मशीन, हाइड्रोलिकपंप और कलपुर्जों पर टैक्स घटने से अब सीमांत किसान भी आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। इससे श्रम लागत कम होगी, समय बचेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। खेती के खर्च में कमी आने से स्वाभाविक रूप से किसान की आमदनी में वृद्धि होगी। ये अनुमानित कीमतें हैं। कंपनियों और राज्यों की नीतियों के आधार पर थोड़ी-बहुत भिन्नता संभव है, लेकिन यह तय है कि किसानों की लागत घटेगी और फायदा निश्चित मिलेगा।

हमारा हर कदम किसानों की समृद्धि के लिए है। किसानों को घटी हुई दरों का लाभ तुरंत मिले, इसके लिए मैंने कृषि मशीन निर्माताओं के संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। यह सुधार केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक संपन्नता और आत्मनिर्भरता के लिए अभिनंदनीय कदम है। कृषि की लागत घटने से किसान अपनी उपज से अधिक लाभ कमा पाएंगे जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। इसका सकारात्मक असर लघु और कुटीर उद्योगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध होगा और उत्पादन लागत घटेगी। साथ ही एमएसएमई क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कृषि और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक हैं। मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन और सहकारी समितियों को GST में जो छूट दी गई है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई समृद्धि आएगी। जब किसानों के खर्च कम होंगे और उनकी आय बढ़ेगी तो वे अपनी जीवनशैली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश कर सकेंगे, जिससे जीवन का चहुंमुखी विकास संभव होगा।

जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष बल रहता है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ रही है, ऐसे में हमारे किसानों को सस्ते दामों पर जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए GST 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने के बजाये धीरे-धीरे जैविक उर्वरकों की ओर बढ़ेंगे। मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, धरती मां का स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ ही किसानों की लागत भी कम होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है इसलिए हम इंटीग्रेटेडफार्मिंग और कृषि संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि किसानों की आय तेजी से बढ़े।

सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसानों के जीवन में समृद्धि का उजाला लाने के लिए मूल्य संवर्धन भी आवश्यक है। जीएसटी सुधारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राहत मिली है। कोल्डस्टोरेज और प्रोसेसिंगयूनिट्स में निवेश बढ़ने से किसानों की उपज लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और प्रसंस्करण के बाद उसे बेहतर दाम मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि वे किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के विरुद्ध किसी भी नीति और समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। आज का यह सुधार उसी संकल्प का प्रमाण है। इससे हमारी विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटेगी और 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर भारत' को बल मिलेगा।

ग्रामीण भारत की समृद्धि का आधार स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें हैं। जीएसटी सुधारों से इन समूहों और एमएसएमई की लागत घटेगी, जिससे गांव और कस्बों में छोटे उद्योग पनपेंगे। ग्रामीण उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए गांवों में प्रसंस्करण ईकाइयां, भंडारण और परिवहन सुविधाएं विकसित होने से विकसित और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा मिलेगी। कर घटने से बिक्री बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा अपने गांव में रहकर ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये सुधार, स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प को सार्थक करेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था 'लॉन्ग लिव इकॉनमी' बनेगी।

ये सुधार केवल कर की दर घटाने भर का निर्णय नहीं हैं, बल्कि किसान, छोटे व्यापारी, पशुपालक, मछुआरे और कुटीर उद्योग चलाने वाली बहनों के जीवन में नई ऊर्जा भरने का पुण्य प्रयास है। हमारी सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' और अंत्योदय के संकल्प के साथ यही सिद्ध कर रही है कि खेत-खलिहान की खुशहाली ही राष्ट्र की प्रगति का पर्याय है। अबकी बार पूरा देश 'स्वदेशी से समृद्धि' के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा। घर-घर स्वावलंबन के दीप जलेंगे, कुटीर उद्योगों से जय स्वदेशी का मंगल स्वर गूंजेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे।

किन्नौर में 12,000 फीट की ऊंचाई पर उच्च घनत्व बागवानी की सफलता का किया प्रदर्शन

शिमला। किन्नौर की ठंडी मरुस्थलीय हंगरंग घाटी के मल्लिंग क्षेत्र में समुद्र तल से 3,556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाई ऐल्टिट्यूड प्रदर्शन बगीचे में सेब दिवस 2.0 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने उच्च घनत्व सेब रोपण प्रणाली और प्राकृतिक खेती की उन उन्नत तकनीकों को प्रदर्शित किया, जो शुष्क समशीतोष्ण जलवायु के लिए विकसित की गई हैं।

यह आयोजन डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किन्नौर और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, शार्बो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

जनजातीय उप-योजना परियोजना (Tribal Sub-Plan Project) के अंतर्गत वर्ष 2021 में स्थापित इस मॉडल बगीचे में सुपर चीफ, स्कारलेट स्पर, रेड वेलोक्स, ऑर्गन स्पर-II और गाला वैल जैसी दस प्रीमियम सेब किस्में सीडिलंग रूटस्टॉक पर लगाई गई हैं। यह बगीचे

अब दुर्गम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उच्च घनत्व बागवानी की संभावनाओं का प्रतीक बन गया है।

कार्यक्रम का शुभारंभ पूह खंड की बीडीसी सदस्य पद्मा दोर्जे, द्वारा किया गया। उन्होंने केवीके और अनुसंधान केंद्र के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उन्नत बागवानी पद्धतियां पहुंचाई हैं।

इस अवसर पर 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सेब उत्पादक, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, बागवानी विभाग और आत्मा के अधिकारी तथा विश्वविद्यालय के बी. एससी. (औद्यानिकी) विद्यार्थी शामिल थे, जो वर्तमान में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (RAWE) कार्यक्रम के तहत किन्नौर में कार्यरत हैं।

इस अवसर पर फल वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. अरुण कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्षेत्र-आधारित नवाचारों का प्रदर्शन किया। सह-निदेशक एवं केवीके किन्नौर के प्रमुख डॉ. प्रमोद शर्मा ने सीडिलंग रूटस्टॉक पर उच्च घनत्व रोपण और प्राकृतिक खेती को अपनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बागीचे प्रबंधन में प्रकृति-आधारित समाधान, बहुस्तरीय फसली प्रणाली और फसल विविधीकरण को दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए आवश्यक बताया।

विषय विशेषज्ञ (औद्यानिकी) देव राज कैथ ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, फसल बीमा, सब्सिडी योजनाओं और जैविक कीट प्रबंधन तकनीकों के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना से जय कुमार ने बताया कि 1,000 से अधिक किसान-जिनमें 99 पूह खंड से हैं-प्राकृतिक खेती क्लस्टर पहल से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि नाको, चांगो, रिब्बा, आसरंग, थांगी और कानम जैसे छह गांवों को प्राकृतिक खेती मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है।

फल वैज्ञानिक डॉ. दीपिका नेगी ने सेब बागानों में स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को शामिल करने की सलाह दी, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। खाद्य प्रणाली विश्लेषक आशीष गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए CETARA प्रमाणन प्रणाली की जानकारी दी और बताया कि यह प्रणाली राज्य में जलवायु-अनुकूल और पारिस्थितिकी कृषि को प्रोत्साहित कर रही है। मगसूल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के निदेशक अजय तन्नीकुलम जो देशभर में 1,500 से अधिक किसानों के साथ बाजार संपर्क और मूल्य श्रृंखला विकास पर कार्य कर रहे है-ने भी अपने अनुभव साझा किए।

प्रगतिशील किसान- शलकर के केसांग तोबदेन और चांगो के कृष्ण चंद ने अपनी प्राकृतिक खेती की सफलता की कहानियां साझा कर अन्य किसानों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए और किन्नौर के सेब उत्पादकों की दृढ़ता और नवाचार की सराहना की।

इस कार्यक्रम में किसानों से जलवायु-सहिष्णु, जल-संरक्षण आधारित और पर्यावरण-मित्र बागवानी प्रबंधन तकनीकों को अपनाने का आहवान किया, ताकि स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

आपदाओं के लिए नहीं, बल्कि लचीलेपन के लिए धन

राजन कुमार शर्मा

इस साल आपदाओं के लिए नहीं, बल्कि लचीलेपन के लिए धन विषय के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 एक निर्णायक बदलाव का आहवान करता है। बाद में आपदाओं के लिए भुगतान से बचने के लिए अभी लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। वित्तपोषण एकमात्र चुनौती है जो आपदा, जलवायु, विकास और मानवीय क्षेत्रों को एकजुट करती है। हर साल बढ़ती आपदाएं, जिनमें से कई जलवायु परिवर्तन से प्रेरित और तीव्र होती हैं, बच्चों और युवाओं की भलाई के लिए खतरा हैं। यूनिसेफ के अनुसार, जलवायु संबंधी आपदाओं सहित जलवायु प्रभावों के कारण दुनिया भर में लगभग एक अरब बच्चे अत्यधिक जोखिम में हैं। 2022 में, चाड, गाम्बिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बाढ़ से प्रभावित बच्चों की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक थी। मृत्यु और चोट के जोखिम से परे, आपदा के बाद बच्चों को स्कूली शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा मुद्दों में व्यवधान जैसे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को आपदाओं से बचाने के लिए, देशों को राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को डिजाइन करते समय उनकी कमजोरियों और जरूरतों पर विचार करना चाहिए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाया जाए और उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान करने के लिए स्थान और तौर-तरीके प्रदान किए जाएं, जैसा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में कहा गया है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा की राजनीतिक घोषणा के कार्यवाही के आहवान के साथ भी संरेखित है, जिसमें युवाओं की पूर्ण, समान, सार्थक और समावेशी भागीदारी और आपदा रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देने का आहवान किया गया है। बच्चों को सशक्त बनाना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम से, उन्हें खुद की रक्षा करने और अपने परिवारों और समुदायों में परिवर्तन के एजेंट बनने में सक्षम बना सकता है, जो उन्होंने सीखा है उसे साझा करके। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विस्तार करने के वैश्विक प्रयास के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। इस साल की अगर बात करें तो उत्तर भारत के जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यो में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भयानक बाढ़, भूस्खलन तथा अन्य तरह की आपदाओं ने भयानक तबाही मचाई है। अगर हम अकेले हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो, यहां पर दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन 20 जून से 19 सितंबर तक एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 427 लोगों की मौत हो चुकी है, और 47 अभी भी लापता है, प्रदेश को लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति, कुल्लू, मंडी कांगड़ा, व किन्नौर जिलों में अधिक तबाही देखने को मिली। वैश्विक आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस वर्ष के IDDRR-2025 का उद्देश्य दो प्रमुख क्रियावली पर केंद्रित है।

सार्वजनिक बजटों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण बढ़ाना। सुनिश्चित करना कि सभी सार्वजनिक विकास और निजी क्षेत्र के निवेश जोखिम-सूचित और लचीले हों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस विषय पर बल दिया है, यह कहते हुए कि वैश्विक सहायता का केवल 2% और अक्सर सरकारी बजट का 1% से भी कम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समर्पित है। यह सिर्फ एक अंतर नहीं है। यह एक गलत गणना है। सुरक्षित स्कूलों और शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा करेंः बच्चों को अपने स्कूलों में सुरक्षित रहने का अधिकार है और इसकी शुरुआत यह सुनिश्चित करने से होती है कि स्कूल आपदा-प्रतिरोधी हों और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों का हिस्सा हों। बच्चों और युवाओं को उनके सामने आने वाले जोखिमों को समझने और उन पर कारवाई करने के लिए आयु-उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रहने के लिए सशक्त बनाएं। इसमें प्रारंभिक चेतावनियों के जवाब में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनकी तैयारी का निर्माण करना शामिल है। सशक्त बच्चे अधिक लचीले समुदायों के लिए परिवर्तन के एजेंट बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिए वैश्विक गठबंधन द्वारा विकसित व्यापक स्कूल सुरक्षा रूपरेखा 2022-2023 का समर्थन और कार्यान्वयन करें, जिसकी अध्यक्षता यूनेस्को और यूनिसेफ करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए 2011 से हर साल आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम अपने 15 वें संस्करण में है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने समस्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य में 1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2025 तक विभिन्न प्रकार की आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को संचालित कर रहा है। जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षित भवन निर्माण संबंधी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी व आभासी बैठकें, सुरक्षित भवन निर्माण मॉडल, आपदा जागरूकता रैलियां, सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री द्वारा प्रचार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व निजी योगदान, सर्वोत्तम गैर सरकारी संगठन, सर्वोत्तम स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं, इसके अतिरिक्त समस्त जिलों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से विभिन्न नृत्य एवं कला मंचों के माध्यम से आपदाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटकों, रैलियां, मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एकमात्र लक्ष्य राज्य में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से आमजन को सुरक्षित एवं जागरूक करना है ताकि इस पर्वतीय क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं से समुदाय एवं अति संवेदनशील श्रेणी के लोगों को भविष्य में सुरक्षित रख पाने में मदद मिल सके। युवा लोग सिर्फ निष्क्रिय पीड़ित नहीं हैं। उन्हें नेता के रूप में सक्रिय भूमिका निभानी है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समाधानों में सहयोग और सह-निर्माण करना है।

निष्कर्ष:अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि आपदाओं को रोकना या कम करना तभी संभव है जब हम लचीलेपन के निर्माण में निवेश करें। केवल आपदा के बाद राहत देने की सोच से बाहर निकलकर, सतत और पूर्वाभासी दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी हम सुरक्षित, समृद्ध और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सकारात्मक सोच से सशक्त हो रहा बागवानी क्षेत्र

सेब सीजन 2025, विपरीत परिस्थितियों में सफलता की इबारत

हिमाचल प्रदेश के बागवानी इतिहास में वर्ष 2025 एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, लगातार मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी दूरदर्शी नीतियों, त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील नेतृत्व के बल पर न केवल स्थिति को नियंत्रित किया बल्कि बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सकारात्मक सोच, पारदर्शी प्रशासनिक दृष्टिकोण और किसान-बागवान केंद्रित नीतियों ने हिमाचल में बागवानी क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की मिसाल पेश की है। भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने के बावजूद वर्ष 2025 का सेब सीजन हिमाचल में बहुत सफल सीजन रहा। राज्य सरकार और बागवानी विभाग ने मिलकर युद्ध स्तर पर सड़कें बहाल कीं जिससे बागवान अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सके।

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार 3 अक्तूबर, 2025 तक कुल 2,60,83,458 सेब पेटियों का कारोबार हुआ जबकि वर्ष 2024 में 1,82,63,874 सेब पेटियों का कारोबार हुआ था। आंकड़े दर्शाते हैं कि इस वर्ष सेब कारोबार में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

दिल्ली की आजादपुर मंडी में हिमाचल के सेब की अत्यधिक मांग रही। ए-ग्रेड रॉयल डिलीशियस 2300 रुपये प्रति 20 किलो पेटी और गोल्डन डिलीशियस 1200 रुपये प्रति पेटी बिकी। यह हिमाचल के सेब की गुणवत्ता, ब्रांड वैल्यू और उपभोक्ता विश्वास का जीवंत प्रमाण है।

मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एचपीएमसी द्वारा इस वर्ष 83,788 मीट्रिक टन सेब की रिकॉर्ड खरीद की गई। मंडी मध्यस्थता योजना की यह अब तक की सबसे बड़ी खरीद में से एक है, जिससे हजारों बागवानों को राहत मिली। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी बागवानी क्षेत्रों में सड़क बहाली कार्य, परिवहन सुविधा और मंडी संचालन में सरकार की तत्परता से बागवानों को उनकी उपज का समय पर और उचित मूल्य मिला।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई। इसमें 22.50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का अंश एवं 2.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है। इस राशि में से 14.50 रुपये करोड़ रुपये किसानों को विभिन्न घटकों जैसे फलों, सब्जियों, मसालों एवं फूलों का क्षेत्र विस्तार, मशरूम उत्पादन, संरक्षित खेती (ग्रीन/पॉलीहाउस), एंटीहेल नेट, फार्म गेट पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग ईकाइयों के लिए वितरित किए गए।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बागवानी प्रदेश की आर्थिक रीढ़, किसानों की समृद्धि और पहाड़ों की पहचान बन चुकी है। यह सकारात्मक परिवर्तन हिमाचल को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बागवानी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

अगले सत्र से प्रदेश में 100 सीबीएसई स्कूल होंगे शुरू: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100

स्कूलों को सीबीएसई पाठयक्रम पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पैटर्न आधारित स्कूलों का अलग रंग होगा और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अलग रंग की वर्दी होगी। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ-साथ मैस का प्रबंध भी किया जाएगा और विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में सीबीएसई के मापदंड पूरा करने वाले अब तक 86 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शेष स्कूलों में सीबीएसई के मापदंड जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। शिक्षा विभाग में खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की समीक्षा भी की और अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एक अच्छा कैम्पस तैयार होना चाहिए, जहां खेलकूद गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त जगह हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

सुक्खू ने कहा कि हर जिला में स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ सभी प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होंगी ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ऊर्जा व्यापार में अहम भूमिका निभाएगा एचपी एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने बिजली की खरीद और

बिक्री को सुचारू रूप से प्रबंधित करने तथा राज्य का राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ बिजली खरीद लागत कम करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र एचपीईएमसी की स्थापना की है।

मुख्यमंत्री एच.पी. एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले सर्दियों के मौसम के मद्देनजर बिजली की खरीद के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है जिससे बिजली उत्पादन घट जाता है। ऐसे में पहले से योजना बनाकर किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एच.पी. एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य को अधिकतम आर्थिक लाभ दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस सेंटर को पूरी पेशेवर दक्षता के साथ कार्य करना होगा ताकि पारदर्शिता और अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस केंद्र को और सशक्त बनाने तथा इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे हासिल करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश प्रजापति, निदेशक एचपीएसईबीएल वित्त अनुराग चंद्र शर्मा, विशेष सचिव शुभकरण सिंह और ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक टीम के साथ एचपी-रेडी परियोजना की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डवेल्पमेंट एंड

डिजास्टर रिकवरी एचपी-रेडी परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना को जनवरी, 2026 से शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव निरंतर बढ़ रहे हैं जिससे मानव जीवन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत पर भारी संसाधन लगाने पड़ रहे हैं।

सुक्खू ने कहा कि विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जा चुका है। इसकी कुल लागत 2,687 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह मिशन न केवल वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे की मजबूती और पुनर्निर्माण कार्य में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी-रेडी परियोजना का उद्देश्य जलवायु-संवेदनशील प्रारम्भिक चेतावनी को सशक्त बनाना, आपदाग्रस्त सड़कों, पुलों और भवनों की मुरम्मत करने के अलावा नालों का तटीकरण करना है। यह परियोजना सशक्त सार्वजनिक सेवाओं के विकास, ग्रीन पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने और जोखिम आधारित सामाजिक सुरक्षा व बीमा तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी। सुक्खू ने किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया ताकि आपदा के दौरान उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के दस स्थानों पर सीए स्टोर बनाए जाएंगे जिससे किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी और आपदा के समय नुकसान से बचा जा सकेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत, विशेष सचिव डी.सी. राणा, परियोजना के लिए विश्व बैंक टीम प्रमुख अनूप करंथ तथा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विजय और शीना अरोड़ा भी बैठक में उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से पूरक पोषाहार की दरों में वृद्धि का अनुरोध किया

शिमला/शैल। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि बाल्यकाल में उचित पोषण के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से कुपोषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरक पोषाहार की दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया ताकि बच्चों के पौष्टिक आहार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस वित्त वर्ष में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 6 अक्तूबर को 66 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है जबकि केन्द्रीय हिस्से के 113 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के वित्त कोष से व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश सरकार को दूसरी किश्त जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा 4013.01 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है जिसमें से 1516.09 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों से केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाते हुए शांडिल ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्री-फेबरिकेटिड ढांचे को भी शामिल किया जाना चाहिए और यह प्रयोग हिमाचल प्रदेश के लिए सफल साबित होगा। उन्होंने केंद्रीय योजना के तहत इनके निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह-स्कूल घोषित किया है ताकि बच्चों को पोषण के साथ-साथ बेहतर देखभाल उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के को-लोकेशन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है।

डॉ. शांडिल ने कहा कि 'पोषण भी पढ़ाई भी' कार्यक्रम के तहत सभी डीपीओ, सीडीपीओ व सुपरवाइजर को स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण करवाया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने डॉ. शांडिल को केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के पांच वाहनों को

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब द्वारा प्रदान की गई इस राहत सामग्री में 161 किट हैं जिनमें सूखा राशन, बर्तन, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। यह सामग्री संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को व्यापक नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बहुमूल्य जानें गई, बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आगे आए विभिन्न संगठनों और लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों में भी हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 की तर्ज पर वर्ष 2025 में भी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई है।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, कांग्रेस नेता सुरेन्द्र मनकोटिया, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश बत्र, मल्टीपल चेयर कॉर्डिनेटर रमन गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट केबिनेट सचिव धीरज जैन, डिस्ट्रिक्ट केबिनेट कोषाध्यक्ष अतुल शर्मा, रीजन चेयरपर्सन रजनीश कतना, शिमला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण वैद, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन डॉ. आर.के. जिष्टू सहित क्लब के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

दीवाली से पहले दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ी, लंबरदारों, एसएमसी टीचर्ज, चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दीवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 5000 रुपये, 877 एसएमसी सी एंड वी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपये, 833 एसएमसी लेक्चरार एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाकर 19,378 रुपये, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 19378 रुपये, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 13762 रुपये, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये किया है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 425 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपये, 1399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 8500 रुपये, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 6300 रुपये, 3304 लंबरदारों के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 4500 रुपये किया है।

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ौतरी की है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय एक हज़ार रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय एक हज़ार रुपये बढ़ाकर 19000 रुपये, जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि के बाद 8300 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये की वृद्धि के साथ इसे 12 हज़ार रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपये बढ़ाकर 9000 रुपये, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 7500 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि के साथ 7500 रुपये, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 5100 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 2100 रुपये किया गया है।

वहीं नगर निगम के मेयर के मानदेय में एक हज़ार रुपये की बढ़ौतरी कर इसे 25 हज़ार रुपये, डिप्टी मेयर के मानदेय में एक हज़ार रुपये बढ़ाकर 19 हज़ार रुपये, पार्षदों के मानदेय में एक हज़ार रुपये बढ़ौतरी कर 9400 रुपये किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये बढ़ौतरी कर 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी कर 8900 रुपये, पार्षदों के मानदेय में 300 रुपये बढ़ौतरी कर 4500 रुपये, नगर पंचायत के प्रधान के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ौतरी कर 9000 रुपये, उप-प्रधान के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ौतरी कर 7000 रुपये तथा नगर पंचायत सदस्य के मानदेय 300 रुपये बढ़ौतरी कर 4500 रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफ़िसर के मानदेय में 300 रुपये, ऑउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपये तथा आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की है।

पर्यावरण संरक्षण की एवज में ग्रीन बोनस का हकदार हिमाचलःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर इस दिशा में तेजी से प्रगति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के विकास के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम पर्यावरण हितैषी होगा। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, उद्योग तथा परिवहन सहित अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदेश सरकार पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूर्ण करने के लिए हमें राज्य की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 90 प्रतिशत नवीकरणीय या हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से हासिल करना होगा। वर्तमान में हमारी ऊर्जा खपत लगभग 14,000 मिलियन यूनिट है और यदि हम 12,600 मिलियन यूनिट नवीकरणीय और हरित ऊर्जा से उपयोग में लाएंगे तभी हिमाचल हरित राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ राज्य के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को होगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों से बदला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप परिवहन क्षेत्र से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अब काफी कम हो गया है। यह पहले लगभग 16-20 प्रतिशत था। इस कदम से प्रदेशवासियों को स्वच्छ और हरित परिवहन सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। निगम द्वारा 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त 124 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं।

इन ई-बसों की खरीद के अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है, जिसके तहत ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इन टैक्सियों की सेवाएं विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थानों में ली जा रही हैं। ई-टैक्सी योजना के तहत अब तक लगभग 50 ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों से जोड़ा जा चुका है। स्टार्ट अप योजना के तहत अब तक 59 पात्र युवाओं को लगभग 4.22 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है और 61 अन्य लाभार्थियों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा बल्कि उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच साल की अवधि के लिए नियमित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत सरकारी विभागों में अटैच ई-टैक्सी को पांच साल के पश्चात अगले दो साल के लिए विस्तार देने का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में छह ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं जिनमें ई-वाहनों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशनों सहित हर सुविधा उपलब्ध है। शीघ्र ही इन कॉरिडोर में 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने ई-वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट और विशेष रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में चल रहे सभी पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को 1,000 बस रूटों पर नए परमिट प्रदान कर रही है। इसके अलावा चिन्हित रूटों पर ई-बसों और टैम्पो ट्रैवलर पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

हिमाचल प्रदेश को 'लंग्ज ऑफ नॉर्थ इंडिया' कहा जाता है और प्राकृतिक संपदा के विस्तार, पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने में प्रदेश के यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा और अनुकूल जलवायु के रूप में देश को अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वनों के कटान से हम प्रदेश के लिए आर्थिक संसाधन जुटा सकते हैं लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के ष्टिगत हम वनों के संरक्षण को महत्त्व देते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र और 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, हिमाचल में पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण के प्रतियोगदान का तकनीकी और वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी, जिसके अनुरूप हिमाचल को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि बढ़ाई गई

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) https://scholarships.gov.in पर आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 अक्तूबर, 2025, आइएनओ स्तर पर जांच, एल-1 की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर, 2025 तथा डीएनओ व एसएनओ स्तर पर जांच, एल-2 की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2025 निर्धारित की गई है।

प्राधिकरण ने नई औद्योगिक व मौजूदा इकाइयों के विस्तार के 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में लगभग 1734.65 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश है तथा लगभग 5388 व्यक्तियों को रोजगार की सम्भावना है जो इस बात को दर्शाता है कि राज्य निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नए प्रस्तावों में माल्ट स्पिरिट ताजा और परिपक्व माल्ट स्पिरिट, जिन, भारत में निर्मित विदेशी तरल, मवेशी चारा के विनिर्माण के लिए मैसर्स एंगस डंडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिला कांगड़ा, सोलर सेल के विनिर्माण के लिए मैसर्स मैनवर्स फार्मा एलएलपी, तहसील पांवटा साहिब, मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3, तहसील बद्दी, मैसर्स जुपिटर सोलरटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स (एक्सेसरीज) के विनिर्माण के लिए मैसर्स मोरपेन मेडिपैथ लिमिटेड, बद्दी, मैसर्स वीरा मोनोकार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, मेसर्स ओपीजी मोबिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3 बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, इंजेक्शन के निर्माण के लिए मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, जिला सोलन, इंजेक्शन निर्माण के लिए मैसर्स ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड, बद्दी, फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन (कैप्सूल) निर्माण के लिए मैसर्ज खुराना ओलेओ केमिकल्स (यूनिट-2), तहसील बद्दी, सोलिनायड वाल्वस निर्माण के लिए लैब्सा, एओएस, एसएलएस, एसएलईएस, सीएपीबी, सीएमईए, ईजीएमएस, ईजीडीएस, बीकेसी, फार्मूलेशन, सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए मैसर्स सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के विनिर्माण के लिए मैसर्ज एनजीजी पावर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तहसील हरोली, जिला ऊना, ऑटो कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील, सीमलेस टड्ब/आउटर ट्यूब, एल्युमीनियम कास्टिंग के विनिर्माण के लिए मैसर्स माइक्रो सीमलेस, तहसील बद्दी, जिला सोलन, बोतलें, अन्य रंगीन सौंदर्य प्रसाधनों के कंटेनर लिपस्टिक मस्कारा आई लाइनर काजल पेंसिल आदि, कैप और क्लोजर, जार के विनिर्माण के लिए मैसर्स यूनिको कॉस्मेटिका प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, बैटरी चार्जिंग और पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बालाजी

एक्सटेंशन, बद्दी, कैप्सूल, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन, टैबलेट 500 एमजी के विनिर्माण के लिए मेसर्स सुपीरियर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, ऑटो स्पेयर पार्ट्स रीयर और फ्रंट एक्सेल शाफ्ट, विभिन्न नली के मामले स्पिंडल स्पूल, संयुक्त क्रॉस पिनियन योक, गियर शाफ्ट, मशीन आटोमोटिव पार्ट्स, पिनियन सपोर्ट क्लच के निर्माण के लिए मेसर्स एम्ब्रोस आटोकाम्प लिमिटेड यूनिट एम्प्रेसिजन, तहसील बद्दी, लोहा और इस्पात के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स और घटकों के निर्माण के लिए मेसर्स डेजर्ट ईगल आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, कॉप्रेस्ड बायो गैस, एफओएम और एलएफओएम जैविक उर्वरक के निर्माण के लिए मेसर्स सीबीजी प्लांट तहसील पांवटा साहिब, मेटलर्जिकल बायोचार और टोरेफाइड बायोमास के निर्माण के लिए मेसर्स बहारी रिन्यूअल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बहारी तहसील धर्मपुर, जिला मंडी, मेसर्स पारस मसाले, तहसील हरोली, आइसक्रीम, अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर मिल्क के निर्माण के लिए शामिल हैं।

बैठक के दौरान प्राधिकरण ने जिन विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की उनमें जूतों के निर्माण के लिए मैसर्स कैम्पस ऐक्टिवियर लिमिटेड बद्दी, करंसी नोट, सुरक्षा पिगमेंट के निर्माण के लिए मैसर्स एरिस्टोक्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पांवटा साहिब, इंजेक्शन, कैप्सूल, मलहम, सिरप, टैबलेट के निर्माण के लिए इंजीनियर्ड फिल्म्स फायल और लेमिनेट, फार्मा पैकेजिंग इंडक्शन वेड मेसर्स यूनाइटेड स्टोरेज बैटरीज लिमिटेड यूनिट-3, पांवटा साहिब, साबुन नूडल्स और साबुन, औद्योगिक मोनोकार्बोलिक फैटी एसिड, आसुत ग्लाइक्राइन, पिच और अवशेष, क्रूड ग्लाइक्राइन के निर्माण के लिए मैसर्स राज इंडस्ट्रीज, तहसील नालागढ़, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के ढक्कन के निर्माण के लिए मेसर्स अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड सिरप, लिक्विड सैशे, लाज़ेंजेस के निर्माण के लिए मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड तहसील बद्दी, इन्फ्यूजन बीएफएस, ग्लास बोतल, लेपित और बिना लेपित टैबलेट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ओरल ड्राई पाउडर सैशे, लिक्विड सिरप सस्पेंशन के निर्माण के लिए मेसर्स हेटविक हेल्थकेयर एलएलपी, तहसील नालागढ़ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रस्ताव में कौशल-वार रोजगार का विवरण शामिल होना चाहिए तथा श्रम-प्रधान एवं हरित उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने ये निर्देश भी दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान पट्टा दरों की समीक्षा भी की जाए तथा औद्योगिक प्लॉट के लिए रूपांतरण नीति भी तैयार की जाए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग आर.डी नजीम, सचिव प्रियंका बासु इंगटी व राखी कहलों, निदेशक उद्योग युनुस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

सोनिया गांधी ने किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

शिमला/शैल। कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने वीरभद्र सिंह के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर कांग्रेस की महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। वह ऐसे शख्स थे, जिनके दिल में हमेशा हिमाचल प्रदेश की भलाई रही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मेरे परिवार का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव है। यहां मेरा सिर्फ घर ही नहीं है, बल्कि मुझे पहाड़ों से भी बहुत लगाव है।

वीरभद्र सिंह को याद करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीति में कम ही मिसाल हैं, जो नेता सचाई पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने देश को और वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को जो रास्ता दिखाया, वही कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है। आज ऐसे नेताओं और राजनीति की जरूरत है जो सोशल मीडिया से आगे बढ़कर लोगों के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी निडर होकर सच बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी की इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसी विचारधारा पर चली है और चलती रहेगी। देश को विकास की राजनीति चाहिए, लेकिन जो केंद्र में सत्तासीन हैं वह इस विचारधारा से दूर है।

कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान सैंकड़ों परिवार उजड़ गये और हर तरफ तबाही मची लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार ने यहां के लोगों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश के आपदा प्रभावितों का दर्द समझते हैं। वह हर जगह गये। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र से मदद मांगी, लेकिन वह प्रदेश को नहीं मिली क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिये हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल आने पर स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें तीस साल तक कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के साथ काम करने का अवसर

मिला। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह से बहुत कुछ सीखा और प्रदेश की जनता उन्हें सड़कों के नेता के रूप में जानती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जबकि भाजपा के नेता 'स्टेटहुड को मारो ठुड' का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गांधी परिवार का ऋणी रहेगा, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की सोच के कारण हिमाचल प्रदेश को आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है, जिससे पर्यटन को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी की देन है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह खुशी की बात है आज वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है और हमारे लिए यह भावुक क्षण है। सोनिया गांधी तथा प्रियंका गांधी ने इस कार्यक्रम मे आकर शोभा बढ़ाई है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का निर्माता बताते हुए कहा कि हम उनकी ही पाठशाला में पढ़े हैं। वीरभद्र सिंह का प्रदेश के लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता था। वह रात 12 बजे तक जन-समस्याएं सुनते थे और हमेशा प्रदेश के लोगों के दुख-दर्द में साथ खड़े रहते थे। वीरभद्र सिंह ने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए जीवन भर काम किया।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया और प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा है। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण मात्र एक औपचारिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जन-भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरना वीरभद्र सिंह की सोच का प्रतीक है। रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के दिखाए आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं।

क्या प्रियंका गांधी अपने गुप्तचरों से सरकार के हाल चाल की जानकारी भी लेगी:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस आला कमान को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो

गारंटियां दी थी उनके बारे में सरकार से एक प्रश्न नहीं पूछा। प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे जिन लोगों ने तीन साल पहले गारंटियां दी थी, आज वह उनका हिसाब भी देंगे। लेकिन सभी नेता सिर्फ इधर-उधर की बात करके चले गये। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए जो कुछ भी हुआ है वह केंद्र सरकार की मदद से ही संभव हुआ है। इसके बाद भी केंद्र सरकार की मदद के लिए उनका आभार जताने के बजाये उन पर ही छींटाकसी की गई। एडीबी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, सभी एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रदेश में लगभग हजारों करोड़ रुपए के जो काम चले हुए हैं, वह क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? क्या उनका 90% हिस्सा केंद्र सरकार नहीं वहन करेगी?

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5500 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को आपदा के नाम पर दी गई है। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज अलग से घोषित किया है। जो सरकार 5500 करोड रुपए केंद्र से लेकर आपदा प्रभावितों को 300 करोड रुपए भी नहीं दे पायी है वह किस मुंह और नैतिकता से केंद्र सरकार से प्रश्न कर रही है। सरकार के लोग चाहते हैं कि पैसा उनकी जेब में आये तो उनकी जेब में केंद्र से पैसा नहीं आएगा। केंद्र से जो भी पैसा आता है वह आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश के भले के लिए आता है। जिसे परियोजनाओं पर ही खर्च करना होता है। हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए 1361 प्रधानमंत्री आवास के लिए 34 करोड़ों रुपए और एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 25 करोड़ केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं। आए दिन हिमाचल प्रदेश को किसी न किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता मिलती रहती है।

जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर तंज करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय हिमाचल प्रदेश के लोगों की राय जानने के लिए अपने गुप्तचरों को लगाया था उसी तरह इस बार भी उन्हें अपने गुप्तचरों को लगा कर इस सरकार के हाल चाल की जानकारी लेंगी तो उनकी आंखे खुल जायेगी। मुख्यमंत्री के संरक्षण में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर किस तरह से व्यवस्था का पतन हो रहा है और तीन साल में हिमाचल किस तरह तीस साल पीछे चला गया, का अंदाजा उन्हें हो जाएगा। प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के आला नेताओं को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर आपदा प्रभावितों से मिलना चाहिए था। हिमाचल सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री यदि आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं प्रभावितों से मिल सकते हैं तो कांग्रेस आला कमान को प्रभावितों से मिलने में क्या समस्या है?

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि प्रियंका गांधी द्वारा हिमाचल में घर बनाना उनका बहुत बड़ा कदम है। इससे हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है। पूरे प्रदेश के लोग उनके दावे से हैरान है। हम भी बहुत सोचने विचारने के बाद भी समझ नहीं पाये कि आखिर प्रियंका गांधी के हिमाचल में घर बना लेने से प्रदेश को क्या फायदा हुआ है? प्रदेश के लोगों को उन्हें यह बात बतानी चाहिए?